

जलवायु अनुकूल कृषि

प्रलिमिस के लिये:

जलवायु-अनुकूल कृषि, FAO, जलवायु परविरतन, जलवायु-अनुकूल कृषिपर राष्ट्रीय नवाचार (NICRA), भारतीय कृषिअनुसंधान परिषद (ICAR), कृषिविनिकी

मेन्स के लिये:

जलवायु-अनुकूल कृषि, जलवायु-अनुकूल कृषिपर राष्ट्रीय नवाचार (NICRA)

सरोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार जलवायु की दृष्टिसे संवेदनशील ज़िलों में स्थिति 50,000 गाँवों में जलवायु-अनुकूल कृषि (Climate Resilient Agriculture-CRA)) को बढ़ावा देने के लिये एक रूपरखा का अनावरण करने की योजना बना रही है।

जलवायु अनुकूल कृषि(CRA) क्या है?

परचिय:

- खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO)) के अनुसार, जलवायु अनुकूल कृषि को "जलवायु और चरम मौसम में परविरतन के प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने तथा उसके लिये तैयारी करने, साथ ही उसके अनुकूल होने, उसे आत्मसात करने एवं उससे उबरने की कृषिप्रणाली की क्षमता" के रूप में परभिष्ठि किया जाता है।

कृषिपर जलवायु परविरतन का प्रभाव:

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research- ICAR) की एक नेटवर्क परियोजना, जलवायु-अनुकूल कृषिपर राष्ट्रीय नवाचार (National Innovations on Climate Resilient Agriculture-NICRA) ने कृषि और कसिनों पर जलवायु परविरतन के प्रभाव का अध्ययन किया।
- अध्ययनों से संकेत मिलता है कि अनुकूलन उपायों की अनुपस्थितियाँ, जलवायु परविरतन अनुमानों से वर्ष 2020-2039 की अवधि के लिये सचित चावल की पैदावार में 3%, वर्षा आधारित चावल की पैदावार में 7 से 28%, गेहूँ की पैदावार में 3.2-5.3%, मक्का की पैदावार में 9-10% की कमी आने की संभावना है और सोयाबीन की पैदावार में 2.5-5.5% की वृद्धि होने की संभावना है।
- सूखे जैसी चरम घटनाएँ खाद्य और पोषक तत्त्वों की खपत को प्रभावित करती हैं, गरीबी को बढ़ाती हैं, पलायन को बढ़ावा देती हैं, ऋणग्रस्तता बढ़ाती हैं तथा कसिनों की जलवायु परविरतन के अनुकूल होने की क्षमता को कम करती हैं।

CRA पद्धति:

- कृषिविनिकी: कृषिविनिकी में फसलों के साथ-साथ पौधों की खेती भी शामिल है, जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार, मृदा अपरदन में कमी तथा जैवविधिता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
 - यह पद्धति मृदा में नमी बनाए रखने में मदद करती है तथा कसिनों को अनेक लाभ प्रदान करती है।
- मृदा एवं जल संरक्षण: कंटूर बंडगि, कृषितालाब और चेक डैम जैसी तकनीकें मृदा में नमी बनाए रखने, मृदा अपरदन को कम करने तथा भू-जल पुनर्भरण को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।
 - ये पद्धतियाँ कसिनों को सूखे और जल की कमी से निपटने में भी मदद कर सकती हैं, जो जलवायु परविरतन के कारण लगातार बढ़ती जा रही है।
- सतत कृषि: फसल विधिकरण, जैविक कृषि और एकीकृत कीट प्रबंधन जैसी पद्धतियाँ रासायनिक इनपुट के उपयोग को कम करने तथा मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करती हैं।
 - इन पद्धतियों से गरीनहाउस गैस उत्तराधिकार में भी कमी आती है तथा कसिनों की आय और खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है।
- पशुधन प्रबंधन: पशुधन प्रबंधन पद्धतियाँ, जैसे स्टाल-फीडगि और मशिरति फसल, पशुधन प्रणालियों की उत्पादकता तथा लचीलेपन में सुधार कर सकती हैं।
 - इन प्रथाओं से प्राकृतिक संसाधनों जैसे चरागाह भूमि पर दबाव भी कम होता है, जो जलवायु परविरतन के कारण दुर्लभ होते जा

रहे हैं।

जलवायु अनुकूल कृषि हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

- सरकार [जलवायु-अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार](#) (NAPCC) का क्रयिन्वयन कर रही है, जो देश में जलवायु कार्रवाई के लिये नीतिगत ढाँचा प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture- NMSA) NAPCC के अंतर्गत भारतीय कृषिको अधिक लचीला बनाने के लिये चलाए जा रहे मशिनों में से एक है।
 - NMSA को तीन प्रमुख घटकों अर्थात् वर्षा आधारित कृषेत्र विकास (Rainfed Area Development- RAD), खेत जल प्रबंधन (On Farm Water Management- OFWM) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (Soil Health Management- SHM) के लिये अनुमोदित किया गया था।
 - इसके बाद चार नए कार्यक्रम शुरू किये गए, जिनके नाम हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC), परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY), पूर्वोत्तर कृषेत्र में जैवकि मूलय शुंखला विकास मिशन (MOVCDNER) और प्रतिबूद्ध अधिक फसल।
 - इसके अतिरिक्त पुनर्गठित [राष्ट्रीय बाँस मिशन](#) (National Bamboo Mission- NBM) अप्रैल 2018 में शुरू किया गया।
- **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** ने जलवायु अनुकूल कृषि प्रदूषणों को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2011 में **राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार** (National Innovations in Climate Resilient Agriculture- NICRA) नामक एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना शुरू की।
 - यह एक बहु-कृषेत्रीय, बहु-स्थानीय कार्यक्रम है जिसका मूल उद्देश्य जलवायु परविरत्न और परविरत्नीयता को संबोधित करना तथा समग्र देश में हतिधारकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है।
 - कृषि और जलवायु परविरत्न से संबंधित कई पहलुओं पर नीतिगत जानकारी प्रदान करने के अतिरिक्त अनुसंधान, प्रदर्शन तथा कृषिमत्ता निर्माण इसके तीन प्रमुख घटक हैं।
 - जलवायु अनुकूल कृषिपर ICAR की प्रमुख उपलब्धियों में 1888 जलवायु उपयुक्त फसल कसिमों का विकास, 650 ज़िलों के लिये ज़िला कृषि आक्समिकिता योजनाओं (District Agriculture Contingency Plans- DACP) का विकास आदि शामिल हैं।
- सरकार ने लघु भू-धारकों सहित कसिमों को जलवायु संबंधी जोखियों से बचाने के लिये वर्ष 2016 के खरीफ सीज़न से उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के सहित [पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना \(RWBCIS\)](#) की शुरुआत की है।
 - इस योजना का उद्देश्य अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं, मौसम की प्रतिकूल घटनाओं के कारण फसल हानि/क्षति से पीड़ित कसिमों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि कृषेत्र में सतत उत्पादन को बढ़ावा देना है ताकि कसिमों की आय में स्थिरिता लाई जा सके।

कृषि से संबंधित अन्य पहल

- [राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन \(NMNF\)](#)
- [मिशन ऑर्गेनिक वैलयू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीज़न \(MOVCDNER\)](#)
- [राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन](#)
- [परंपरागत कृषि विकास योजना \(PKVY\)](#)
- [कृषिवानकी उप-मिशन \(SMAF\)](#)
- [राष्ट्रीय कृषि विकास योजना](#)
- [एग्रीस्टेक](#)
- [डिजिटल कृषि मिशन](#)
- [एकीकृत कसिम चैवा मंच \(UFSP\)](#)
- [कृषि राष्ट्रीय ई-गवरनेंस योजना \(NeGP-A\)](#)
- प्रधानमंत्री 'नमो ड्रोन दीदी' योजना

जलवायु अनुकूल कृषि से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- [विकासशील देश](#) जलवायु जोखियों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं क्योंकि वे प्रमुख रूप से कृषिपर निभिर हैं तथा जोखिमि प्रबंधन के लिये आवश्यक प्रौद्योगिकियों का अभाव है। उदाहरण हेतु भारत में 65% जनसंख्या कृषि और सबदध गतिविधियों में लगी हुई है।
 - जोखियों को कम करने और अनुकूलन उपायों के अभाव के कारण ये गरीब कसिम नमिन आय, उच्च ऋण तथा गरीबी के चक्र से उबर नहीं पाते हैं।
- वर्तमान में MSP व्यवस्था कुछ फसलों पर केंद्रित है जिसमें अन्य फसलों के लिये प्रयाप्त सहायता नहीं दी जाती है। जिसके परणिमस्वरूप फसलों का विविधीकरण कम होता है।
- वशीष रूप से उत्तरी भारत में भू-जल पर अत्यधिक निभिरता से सतत कृषि के कृषेत्र में किये गए प्रयासों की प्रभावशीलता कम होती है।
- कृषि कृषेत्र का देश के ग्रीनहाउस गैस उत्पादन में लगभग 14% योगदान है और सधिटकि [नाइट्रोजन उत्पादकों](#) के उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड उत्पादन दर में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
- भारत की कृषि उत्पादकता अन्य प्रमुख उत्पादकों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, जहाँ प्रति हेक्टेयर चावल की औसत उपज लगभग 2.5 टन है जबकि चीन में प्रति हेक्टेयर औसतन लगभग 6.5 टन है।
- जलवायु परविरत्न नीति का सबसे चुनौतीपूरण राजनीतिक पहलू ग्राम पंचायतों या स्थानीय स्वशासी निकायों द्वारा अप्रयाप्त मान्यता है, जिसके

कारण ज़मीनी स्तर पर नीतिगत पहल का अभाव है।

आगे की राह

- विकासशील देशों पर जलवायु परविरतन के प्रतिकूल प्रभाव को तकनीकी उन्नति, मौसम विज्ञान और डेटा विज्ञान जैसे एकीकृत दृष्टिकोणों के माध्यम से कम किया जा सकता है।
 - जलवायु और मौसम संबंधी घटनाओं से कसिनों की रक्षा के लियाराष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषिनिवाचार (NICRA) योजना को सभी जोखिम-संवेदनशील गाँवों में लागू किया जाना चाहिये।
- **फसलों के विविधीकरण** की आवश्यकता है जो कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को जलवायु परविरतन के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाएगी।
 - फसल विविधिता खाद्य सुरक्षा सुनिश्चिति करने, पुदा की उत्तरता बढ़ाने, कीटों को नियंत्रित करने और उपज स्थरिता लाने में भी मदद करती है।
- **डुरपि सचिवाई** के दायरे में न केवल उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों अपत्ति अन्य फसलों को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- सरकार को भू-जल निषिकरण के संदर्भ में बजिली सबसेडी पर सावधानीपूर्वक पुनरविचार करना चाहिये, क्योंकि भू-जल स्तर में कमी आने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है।
 - सचिवाई कार्यक्रम को अनुकूलति करने, जल को संरक्षित करने तथा प्रयावरणीय प्रभाव को कम करने वाले उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिये।
- चूंकि जैवकि खेती में गरीनहाउस गैसों को कम करने की क्षमता होती है, इसलिये संबंधित मंत्रालय द्वारा जलवायु परविरतन के अनुकूल जैवकि खेती को बढ़ावा देना चाहिये।
 - जैवकि खेती में नाइट्रोजन उत्तरक का उपयोग प्रतिबंधित होने से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है।
- **कृषिविज्ञान केंद्रों (KVK)** के बुनियादी ढाँचे के साथ तकनीकी सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। उन्हें स्थानीय भाषाओं में जानकारी प्रदान करने के लिये तकनीकी नवाचारों का उपयोग करना चाहिये। ये परविरतन मौजूदा KVK को नया रूप देने के साथ उन्हें जलवायु संबंधी चुनौतियों का सम्मान करने के लिये सुसज्जित करेंगे।
- जलवायु-अनुकूल फसल कसिमों को अपनाने और उनका प्रसार करने के क्रम में सारांशनकि निविश बढ़ाने की आवश्यकता है। इन फसलों में तापमान तथा वर्षा के उत्तर-चढ़ाव के प्रतिस्थिति की अधिक होने के साथ जल और पोषक तत्त्वों का अनुकूल उपयोग सुनिश्चित होगा।
 - कृषि नीतिके तहत फसल उत्पादकता में सुधार को प्राथमिकता देने के साथ जलवायु परविरतन से उत्पन्न जोखिमों से निपटने हेतु सुरक्षा संचाल तैयार किया जाना चाहिये।
- जलवायु परविरतन के क्षेत्र में प्रशासन द्वारा किये गए प्रयासों से तब वांछति प्रणाली नहीं मिल सकते हैं जब तक कि स्थानीय शासन को कृषि नीति-निर्माण में शामिल नहीं किया जाता है।
 - चूंकि प्रशासनों के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में, नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये।
 - जलवायु के प्रतिस्थिति अनुकूलनीय पद्धतियों को अपनाने वाले गाँवों हेतु राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर रैकिंग प्रणाली शुरू करने से ऐसी पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहन मिल सकता है।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न: जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को बताते हुए इन चुनौतियों के समाधान हेतु उपाय बताइए?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्ष के प्रश्न

????????????????????:

प्रश्न: जलवायु-अनुकूल कृषि (क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में, नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत में 'जलवायु-समारट गराम (क्लाइमेट-स्मार्ट वलिज)' दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम-जलवायु परविरतन, कृषिएवं खाद्य सुरक्षा (सी० सी० ए० एफ० एस०) द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है।
2. सी० सी० ए० एफ० एस० परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु प्रामर्शदात्री समूह (सी० जी० आइ० ए० आर०) के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है।
3. भारत में स्थिति अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (आइ० सी० आर० आइ० ए० एस० टी०), सी० जी० आइ० ए० आर० के अनुसंधान केंद्रों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

Q. 'जलवायु-अनुकूली कृषकों के लिये वैश्वकि सहबंध' (ग्लोबल एलायन्स फॉर क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर)

(GACSA) के संदर्भ में, नमिनलखिति में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. GACSA, वर्ष 2015 में पेरसि में हुए जलवायु शिखिर सम्मेलन का एक परिणाम है।
2. GACSA में सदस्यता से कोई बंधनकारी दायतिव उत्पन्न नहीं होता।
3. GACSA के नियमान में भारत की साधक भूमिका थी।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनायिः

- (a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1,2 और 3

उत्तरः (b)

/?/?/?/?/?:

प्रश्नः एकीकृत कृषिप्रणाली (IFS) कृषिउत्पादन को बनाए रखने में किसी सीमा तक सहायक है? (2019)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/climate-resilient-agriculture-1>

